(1) Name of the course :- (i) BA Part I - ECONOMICS Hons. Paper-II (Indian Economy)

(2) Paper :- (ii) BA (ECOH), Part III Paper VII (Agr. Eco.)
(iii) Paper-V (Development & Environmental Economics)
BA Part II, Paper - Economics Subsidiary

(3) TOPIC :- UNEMPLOYMENT IN INDIA & TYPES of UNEMPLOYMENT

(4) Written by :-

Dr. (Prof.) - DURGA NAND JHA
COURSE CO-ORDINATOR, ECONOMICS
NOU

UNEMPLOYMENT & Types of UNEMPLOYMENT IN INDIA
बेरोजगारी व भारत में बेरोजगारी के प्रकार

जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है शारीरिक रूप से कार्य करने में योग्य (समर्थ) होता है परन्तु उसे प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई कार्य नहीं मिलता, जिससे वह अपनी आजीविका कमा सके, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को बेरोजगार कहते हैं।

भारत एक विकासशील देश है। इस कारण यहाँ बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की अपेक्षा भिन्न है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड केन्स के अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण प्रभावी मांग का अभाव है। श्रम की मांग उद्योगों के उत्पादन की मांग में कमी हो जाने के कारण गिर जाती है। इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। जिसे दूर करने के लिए केन्स महोदय ने 1936 में (अपनी पुस्तक Gen Theory) प्रभावी मांग को पर्याप्त स्तर पर ऊँचा रखने का सुझाव दिया।

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के दो पहलू है—
मौसमी तथा निरन्तर। एक अनुमान के आधार पर वर्ष में लगभग 5 से 7 मास तक के लिए ग्रामीण श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग बेरोजगार रहता है। ऐसी श्रम शक्ति अधिकतर कृषि कार्य अथवा सड़क व भवन निर्माण में अपना योगदान देती है।

ग्रामीण बेरोजगारी का दूसरा पहलू भारतीय कृषि के निरंतर अल्प रोजगार या चिरकालीन छिपी बेरोजगारी का विद्यमान होना है। चूंकि भूमि पर निर्भर कार्यकारी जनसंख्या में वृद्धि के साथ कृषि-योग्य क्षेत्र में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई अतः कृषि में जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो गई। यदि इस अतिरिक्त जनसंख्या (जनाधिक्य) को कृषि कार्य से हटा लिया जाय तो भी कृषि-उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं ~~पड़ेगा~~ पड़ेगा अर्थात ऐसे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।

भारत में नगरीय बेरोजगारी की समस्या के दो रूप हैं-
(1) औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी एवं (2) शिक्षित मध्यम वर्ग में बेरोजगारी।

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण सक्रिय जनसंख्या (working) में वृद्धि, नगरीकरण के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन आदि ऐसे कारण हैं जिनसे औद्योगिक श्रमिकों की संख्या रोजगार के अवसरों की तुलना में बढ़ जाती है। दूसरे प्रकार की नगरीय बेरोजगारी शिक्षित मध्यम वर्ग में पायी जाती है। शिक्षित लोग ऐसे कार्य खोजते हैं जिसमें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश भारत जैसे देश में उस प्रकार के कार्य का सृजन काम-चाहने वालों की तुलना में बहुत कम है अतः वे बेरोजगार रहते हैं।

भारत में बेरोजगारी के प्रकार:—

भारत में बेरोजगारी एक दीर्घकालीन बिमारी है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने से यह समस्या दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। भारत में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार की ~~बेरोजगार~~ बेरोजगारी विवरण निम्नलिखित है:—

① **संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural unemployment):-**

सीमित पूंजी तथा श्रम का बाहुल्य इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है। भारत में पूंजी के साधन सीमित हैं तथा जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अतः यहां विकासशील अर्थव्यवस्था सब लोगों को रोजगार देने में असमर्थ रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है।

② **अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised unemployment):-**

मुख्यतया भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पायी जाती है। भारतीय कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती से हटाकर अन्यत्र लगा दिया जाये तो कृषि उत्पादन में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार देखने में तो ऐसा लगता है कि सब लोगों को रोजगार मिला हुआ है, परन्तु वास्तविकता यह है कि यहां अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है।

③ **मौसमी बेरोजगारी (Seasonal unemployment):—**

मौसमी बेरोजगारी भी कृषि में पायी जाती है। भारत में कृषि मजदूर को वर्ष भर कार्य नहीं मिलता। जुताई, बुआई, कटाई के समय कृषि कार्य में दिन-रात काम रहता है और बीच के समय काम कम रहता है। इस प्रकार वर्ष में कुछ समय श्रमिक बेरोजगार रहते हैं। इसी प्रकार चीनी उद्योग के व्यवसाय में काम करनेवाले श्रमिकों को वर्ष में 5 माह काम रहता है और शेष महीनों में वे खाली रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।

④ **अर्द्ध बेरोजगारी (Under Employment):—**

देश में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें काम तो मिला हुआ है किन्तु उस काम में उनकी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, इन्जीनियरिंग की डिग्री प्राप्त व्यक्ति एक लिपिक के रूप में कार्य करता है तो इसको अर्द्ध बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार कहते हैं।

5. प्रावैधिक बेरोजगारी (Technological unemployment):—

जब कभी व्यवसायों में उच्चस्तरीय प्राविधिक उन्नति हो जाती है तो श्रमिकों को नया तकनीक सीखने में जितना समय लगता है, उतने समय वे बेरोजगार रहते हैं। दूसरे वे व्यक्ति भी बेरोजगार रहते हैं, जिनके काम (तकनीक) की मांग नहीं होती।

6. चक्रीय बेरोजगारी (cyclical unemployment):—

जब व्यापार चक्र में मन्दी का काल आता है तो वस्तुओं की मांग कम हो जाती है जिस कारण बहुत से श्रमिकों को काम से निकाल दिया जाता है। 2020 के विश्वव्यापी CORONA के कारण बहुत से उद्योग धन्धों को बन्द करना पड़ा, प्रत: मांग कम हो गयी और लोग बेरोजगार हो गये।

7. शिक्षित बेरोजगारी (Educated unemployment).

जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार कार्य नहीं मिलता और बेरोजगार रहते हैं तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत पायी जाती है।

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी समाज अथवा अर्थव्यवस्था में गरीबी एक आवश्यक बुराई है तो बेरोजगारी एक सिर दर्द। यदि समाज के सभी इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा तो गरीबी स्वत: ही समाप्त हो जायगी।

— X —

1. Name of the course :— ECONOMICS
2. paper :-
   (1) BA part I(H) paper II - Indian Economy
   (2) BA part II, paper II - Eco subsidiary
   (3) BA part III, Eco(H), paper-V (Dev. & Environmental Eco)
   (4) BA Eco(H), part III paper — VII (Agricultural ECONOMICS)

3. Title :- causes of unemployment in India
4. written by :- Dr. (Prof.) Durga Nand Jha
   course co-ordinator, ECONOMICS
   NOU

causes of UNEMPLOYMENT

भारत में बेरोजगारी के कारण।

(1) जनसंख्या में वृद्धि (Increase in population) —

भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना है। भारत में 1950-51 में कुल आबादी 36 करोड़ थी जो 2020 ई. में बढ़कर लगभग 135 करोड़ पहुंच गई। रोजगार के बढ़ने की दर श्रम शक्ति के बढ़ने की दर से बहुत ही कम है अन्ततः यह खाई (gap) ही बेरोजगारी है।

(2) सीमित भूमि (Limited Land Area) :—

भारत में 14.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में कृषि की जाती है। इतनी ही भूमि की मात्रा पर बढ़ती हुई आबादी का अधिक हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ है। जिस कार्य को व्यक्ति कर सकता है उसमें 5 व्यक्ति लगा हुआ है।

(3) कृषि की मौसमी प्रकृति (Seasonal Nature of Agriculture)

भारतीय कृषि एक मौसमी व्यवसाय है जिस कारण श्रमिकों को कृषि कार्य में वर्षपर्यन्त रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अनुमानतः भारत में जुताई, बुआई व कटाई मिलाकर 5-7 महीने काम रहता है।

(4) कृषि मानसून पर जुआ है (Gample on Rains):—
कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 40-45% भाग में सिंचाई की सुविधा है। शेष आधे से अधिक भाग भगवान भरोसे रहता है। वर्षा समय पर न हुई। अति वृष्टि या अनावृष्टि हुई तो फसल बरबाद हो जाती है और अधिक करोड़ों की संख्या में बेकार हो जाते हैं।

(5) अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक कृषि (Unorganised and unscientific Agriculture)

(6) खेतों का छोटे और टुकड़ों में होना (Sub-division and Fragmentation of Land holdings)

(7) कुटीर उद्योग-धन्धों का अभाव (Lack of cottage industries)—

(8) कृषि का यन्त्रीकरण (Mechanisation of Agriculture):—

(9) दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन (Defective Economic planning)

(10) पूंजी की कमी (Lack of capital)—

(11) औद्योगिक विकास का अभाव (Lack of Industrial Development):—

(12) Faulty Education system (दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली):—

(13) दोषपूर्ण विचार पद्धति (Defective Thinking):—

(14) ग्रामीण सामाजिक विघटन (Rural social Disorganisation)

(15) आर्थिक विकास की कमी (Lack of Economic Development)—

(16) आर्थिक प्रगति की कमी (Lack of Economic Progress)—

(17) कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का अभाव (Absence of employment opportunities other than Agriculture)

(18) संयुक्त परिवार प्रणाली (Joint Family system) —

बेरोजगारी दूर करने के उपाय (Measure to Eradicate Unemployment):—

(1) सहायक और अनुपूरक उद्योगों का विकास (Growth of subsidiary Industries)

(2) कृषि के अलावा नये क्षेत्रों का विकास (Development of New sectors other than Agr

(3) जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण (control on population growth)—

(4) सामाजिक सेवाओं का विस्तार (Expansion of social services) (5) अन्तरसंरचना का विकास (Growth of Infrastructure) (6) घरेलू बचत व निवेश की बढ़ोत्तरी (Increase in Domestic savings & Investment) (7) लघु सिंचाई योजनाओं का विकास

(8) औद्योगिक विकास (Industrial Development) (9) शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन (10) जन शक्ति आयोजन (Manpower planning)

(11) लघु उद्योगों को प्रोत्साहन (Encouragement to small Entesprises)

(12) सही तकनीकि चुनाव का चयन (selection of Appropriate choice of Technique)

—X—

1. Name of the course :- ECONOMICS
2. PAPER :-
   1. MA PART I, paper-VI (Economics of growth Development & planning)
   2. MA Part I, Paper V (Indian Economy)
   3. BA Eco (H) - PART III Paper-V (Development & Environmental Economics)
   4. BA PART I - PAPER-II (Indian Economy)
3. Title :- Economic Planning, Definitions, characteristics & objectives of Eco. planning
4. Written by :- Dr (Prof.) DURGA NAND JHA

COURSE CO-ORDINATOR, ECONOMICS

NOU

ECONOMIC Planning :- Definitions, characteristics & objectives of Economic planning

प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी परिभाषाएँ निम्नवत है :—

(1) प्रो० हेयक के अनुसार - "आर्थिक नियोजन से आशय केन्द्रीय सत्ता द्वारा उत्पादक क्रियाओं का निर्देशन है।"

(2) प्रो० L. Robbins के अनुसार - "नियोजन से आशय उत्पादन पर किसी प्रकार के राजकीय नियन्त्रण से है"।

(3) Dalton के अनुसार - "आर्थिक नियोजन अपने विस्तृत अर्थों में विशाल साधनों के संरक्षक व्यक्तियों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है"।

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में -

(i) लक्ष्यों का पहले से निर्धारण किया जाता है,

(ii) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन किया जाता है और

(iii) यह ~~निर्दे~~ निर्देशन विशाल साधनों के संरक्षक व्यक्तियों अर्थात सरकार किया जाता है।

(4) गुन्नार मिर्डाल के अनुसार - "आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की व्यूह रचना का एक कार्यक्रम है जिसमें बाजार के व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाने के प्रयास किये जाते हैं।"

(5) Mrs. Barbara Wootton के अनुसार — "आर्थिक नियोजन से तात्पर्य सार्वजनिक अधिकारी द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं का सचेत, विवेकपूर्ण तथा इच्छानुसार किया गया निर्वाचन एवं निर्धारण है।"

(6) प्रो. वाटरसन के शब्दों में — "नियोजन विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम विकल्प का संगठित, सुविचारित एवं सतत प्रयास है"।

(7) भारतीय योजना आयोग के अनुसार — "आर्थिक नियोजन निश्चित रूप सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध साधनों का संगठन लाभकारी रूप से उपयोग करने की एक मात्र विधि है।"

(8) राष्ट्रीय नियोजन समिति के शब्दों में — "आर्थिक नियोजन उपभोग, उत्पादन, विनियोग, व्यापार तथा राष्ट्रीय लाभांश के वितरण से सम्बन्धित स्वार्थ रहित विशेषज्ञों का तकनीकी समन्वय है जो राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा ~~कि~~ पूर्व निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त किया जाये।"

Characteristics of Economic Planning (आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ) —

(1) आर्थिक संगठन की एक प्रणाली (System of Economic organisation) : —

आर्थिक ~~नियोजन~~ संगठन की यह प्रणाली स्वतंत्र उपक्रम की पूंजीवादी प्रणाली की वैकल्पिक पद्धति है। अर्थव्यवस्था के सभी विभागों — उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व की प्रक्रियायें नियोजन का विषय होती हैं तथा कृषि, उद्योग, यातायात, व्यापार समाज सेवा इत्यादि सभी कार्य आर्थिक नियोजन के अनुसार संचालित होते हैं।

(2) केन्द्रीय नियोजन सत्ता (Central Planning Authority) —

आर्थिक नियोजन में एक केन्द्रीय नियोजन सत्ता की स्थापना की जाती है। इस सत्ता का कार्य योजनाएँ तैयार करना तथा इन्हें क्रियान्वित करने हेतु संगठन सम्बन्धी उचित व्यवस्था करना होता है।

(3) पूर्व निर्धारित उद्देश्य (Pre-determined objectives) : —

नियोजन में उद्देश्य को पहले से ही खूब सोच-समझ कर निर्धारित कर लिया जाता है। प्रायः ऐसे उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं जो देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, जैसे — रोजगार सृजन में वृद्धि, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, धन एवं सम्पत्ति की असमानता को दूर करना, गरीबी ~~तथा~~ अशिक्षा दूर करना, शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना, आदि।

(4) निश्चित समय (specific period) :- आर्थिक नियोजन के कार्यक्रम निश्चित समय की अवधि के सन्दर्भ में तैयार किये जाते हैं और निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं को निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास किया जाता है

(5) साधनों का विवेकपूर्ण गणना एवं प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन (Rational calculation and allocation of Resources on the basis of priorities)

(6) दीर्घकालीन प्रक्रिया (Long term process) (7) control (नियन्त्रण)

Objectives of Economic planning
आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

(1) आर्थिक उद्देश्य

1. राष्ट्रीय संसाधनों का उचित प्रयोग (Proper utilisation of National Resources)
2. पूर्ण रोजगार (Full employment)
3. Economic Equality (आर्थिक समानता)
4. आय के वितरण की असमानता में कमी (Reduction of Disparities of distribution of Income & wealth)
5. अधिकतम उत्पादन (Maximum Production)
6. तीव्र औद्योगिक विकास (Rapid Industrialisation)
7. संतुलित विकास (Balanced growth)
8. आर्थिक सुरक्षा (Economic security)
9. आत्म निर्भरता की प्राप्ति (Attainment of self-reliance)
10. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development)
11. आर्थिक स्थायित्व (Economic stability)
12. कीमत-स्तर में स्थिरता (Stability in Price-level)

(2) सामाजिक उद्देश्य

1. सामाजिक सुरक्षा (social security)
2. सामाजिक समानता (social Equality)
3. सामाजिक न्याय (social justice)
4. नैतिक स्तर में वृद्धि (Increase in Moral-Level)
5. कल्याणकारी राज्य की स्थापना (Establishment of welfare state)

(3) राजनैतिक उद्देश्य

1. राष्ट्रीय सुरक्षा (National Defence)
2. शान्ति (Peace)
3. आधुनिकीकरण (Modernisation)
4. राजनैतिक स्थायित्व (Political stability)
5. लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा (security of Democratic values)

— X —

Name of the course :- ① BA ECONOMICS(H), PART-1
Paper - Paper-1 (Micro Economics)
② BA Economics (Subsidiary) PART-1
Paper-1 (MICRO ECONOMICS)

Title :- Consumer Behaviour - UTILITY ANALYSIS
Assumption, LDMU, consumer's Equilibrium

Written by :- Dr. (Prof.) DURGA NAND JHA
COURSE - Co-ordinator
ECONOMICS,
NOU

MARSHALLIAN UTILITY ANALYSIS

... the consumer should ... their ... the buys that commodity first which yields the highest utility, and the last which gives the least utility.

(2) LIMITED Money Income to spend on the goods he/she chooses to consume. Limitation of Y, along with U. Max objective makes the choice between goods inevitable

(3) Max. of satisfaction. Every rational consumer intends to max. his/her satisfaction from his given MY.

(4) cardinalists have assumed that U is cardinally measurable and that U of one unit commodity = the units of money which a consumer is prepared to pay for it.

1 UTIL = 1 Unit of Money.

(5) Diminishing Marginal UTILITY - this is an axiom of consumer theory

(6) constant Marginal utility of Money cardinal Utility approach assumes that MUm remains constant whatever the level of consumer's income ∴ cardinalist's used money as a measure of utility

(7) Utility is additive - consumer consumes - X1 X2 X3 ... X3, derives, U1, U2, U3 ... Un Utils respectively. TU that the consumer derives from n units of commodity x

$$U_n = U_1(X_1) + U_2(X_2) + U_3(X_3) + \ldots + U_n(X_n)$$

CONSUMER'S EQUILIBRIUM - Cardinal U approach

Technically a U. max. consumer reaches his equilibrium position when allocation of his expenditure is such that the last Rupee/penny spent on each commodity yields the same utility.

C. Equilibrium - one commodity model

consumer with a given MY consumes only one commodity & ∴ Both his MY & Commodity X have utility for him. He can spend his MY on c(X) or retain it in the form of Asset. If $MU_x > MU_m$, A U. max. consumer will exchange his MY for the goods X. By assumption MU_x is subject is L.D. Return, where MU_m is constant

Assumption
Law of D.M.U. holds true only under certain conditions - referred to as the assumption of the Law. —

1. the Unit of the consumer good must be STANDARD ONE. ie. a cup of tea, a bottle of cold drink. If the units are excessively small or large.
2. the consumer's taste or preference remain the same during the period of consumption.
3. there must be continuity in consumption, when a break in continuity - appropriately short
4. A mental condition of the consumer must remain normal during the period of consumption. A person drinking wine may feel greater pleasure in the successive pegs because of change in mental status due to intoxication

Given these conditions, the LDMU holds universally. In some cases, collection of hobbies, like STAMPS, old coins, rare paintings ..... - MU may initially increase rather than decrease. But eventually it does decrease.

CARDINAL UTILITY - Neo classical Economists, to believe that U is measurable and cardinally quantifiable. U can be assigned cardinal numbers like, 1, 2, 3, etc.

Neo-C. Eco. developed the theory of consumption on the assumption that U is cardinally measurable. They coined the term "UTIL" meaning UNITS OF UTILITY. In this meaning they assumed that:

(i) one util = one unit of money
(ii) the UTILITY of MONEY remains constant.

Analysis of CONSUMER BEHAVIOUR - based on cardinal UTILITY ANALYSIS
- theme of C. theory - is the U Max. behaviour of a consumer
The specific questions that the C. theory seeks to answer are

(i) How does a consumer decide the optimum quantity of a commodity that he or she chooses to consume, i.e. How does a consumer attain Equilibrium in respect to each commodity?
(ii) How does he or she allocate his/her disposable Y between various commodities of consumption so that his/her TU is maximised?

This theory Consumer behaviour seeks to answer these questions on the basis of the postulate the consumer seeks to maximise their TU.

Technically a U max. consumer reaches his equilibrium position when allocation of his exp. is such that last rupee spent on each C yields the same UTILITY.

Consumer's Equilibrium – One commodity model

Consumer with a given MY consumes only one commodity – X

∴ Both his MY & C(X) have UTILITY for him.

He can
(i) either spend his MY on C(X)
(ii) or retain it in the form of asset.

If $MU_x > MU_m$,
for the a U. max. consumer will exchange his MY for commodity X. By assumption – (i) MU_x is subject to L.D.R. & (ii) MU_m remain constant

~~$MU_x > P$~~

∴ the consumer will spend his MY on C(X) so long as $MU_x > P_x (MU_m)$, [P_x is – Price of C(X) & $MU_m = 1$ constant]

The U. max. consumer reaches his equilibrium i.e. the level of satisfaction, where,

$MU_x = P_x (MU_m)$. Alternatively consumer reaches his equilibrium where.

$$\frac{MU_x}{P_x(MU_m)} = 1$$

Graphical repr. of c's equi.

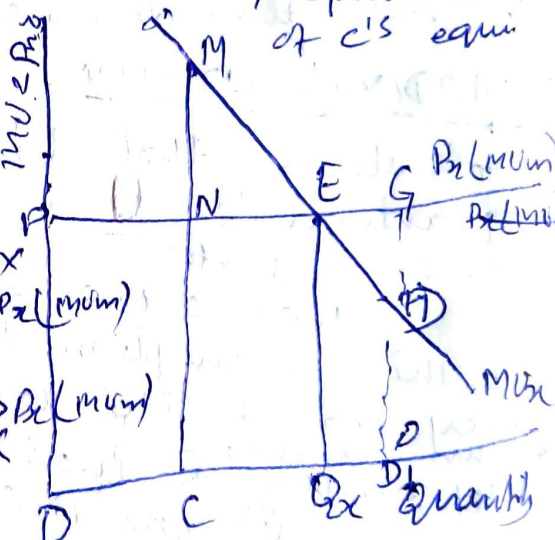

Horizontal line $P_x(MU_m)$ shows constant MU_m weighted by P_x

MU_x curve – diminishing MU of x

Both line intersects at E. [$MU_x = P_x(MU_m)$]

Equi Q_x – OQ_x

At any point above E, M, $MU_x > P_x(MU_m)$

∴ c will exchange his MY for X will increase his TU.

$MU_x = MC$, $P_x = NC$ } marginal gain = MC – NC = MN

At any point below E

D, $MU_x = DD'$, Price $= GD'$ } loss = GD

C's Equi – MULTIPLE COMMODITY MODEL

one C(X) – unrealistic assumption. In real life C consumes large No. of goods so question arises how does a consumer consuming m. goods reach his equilibrium? – (i) C has LMY & (ii) U he derive from various Cs is L.D.R.

We also know that MU schedule of various Cs may not be the same. Some Cs yield higher MU & some lower for the same no. of units consumed. In some cases MU decreases more rapidly than in case of others.

A rational & U. max. consumer consumes Cs in order of their utilities. He/she first picks up the commodity which yields the highest Us followed by C yielding second highest ... and so on.

He switches his exp. from one commodity to another in accordance with their MUs, till he reaches a stage where MU of each C is the same per unit of expenditure – this is called Law of equi-MU.

L of Equi MU states that a consumer consumes various goods in such a quantities that MU derived per unit of exp. from each good is the same.

In other words, a rational consumer spends his MY on various goods, he consumes in such manner that each rupee spent on each good yields the same MU.

following for simplicity – Two Cs – X & Y, P_x & P_y. Equilibrium rule of single commodity, the C will spend his MY of X & Y in such proportion that (3)

$$MU_x = P_x(MU_m), \quad MU_y = P_y(MU_y)$$

given these condition – C's equi – can be expressed as

$$\frac{MU_x}{P_x(MU_m)} = 1 = \frac{MU_x}{P_y(MU_m)} \quad [\because MU_m = 1] \quad \text{......(1)}$$

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} \text{ or } \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

Eq(1) leads to the conclusion C reaches his equi – when MU derived from each rupee spent on the 2 commodities X & Y is the same. It reveals that consumer is in equi when MU ratio of any 2 goods equal their price ratio. If A to Z good can be generalised.. Equi – condition – may be expressed

$$MU_A/P_A = \frac{MU_B}{P_B} = \cdots = \frac{MU_Z}{P_Z} = MU_m$$ – L of Equi MU

In order to achieve equilibrium what a U. Max. consumer intends to equalise is not the MU of each commodity he consumes, but the MU per unit of his money expenditure on various goods & services.